



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2019/माघ 12, 1940

No. 522]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019/MAGHA 12, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

सं. 01/2019-केंद्रीय कर

**का.आ. 635(अ).**—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि —

- (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;
- (ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य या संघराज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

और, कारबाह पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रूप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरूप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 3330 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित संघराज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017, संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है।
  2. कठिनाईों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --
- (i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दसूरे परंतकु के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;
  - (ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग II)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)  
**ORDER**

New Delhi, the 1st February, 2019

**No. 01/2019-Central Tax**

**S.O. 635(E).**—WHEREAS, sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that-

- (i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;
- (ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent. of turnover in a State or Union territory in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if, save as otherwise provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of section 10;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Central Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017, No. 01/2017-Central Tax, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 3330 (E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely: —

1. **Short title.**—This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account -
- for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10;
  - in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition Scheme.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

### सं. 01/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर

**का.आ. 636(अ).**—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 यह उपबंधित करती है कि--

- एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;
- (ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 यह उपबंधित करती है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है; और, कारबाह पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रूप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहाँ तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरूप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 3329 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017, संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिश पर, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- इस आदेश का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है।
  - कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहाँ तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --
- उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के दसूरे परंतु के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;
  - कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग II)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 1st February, 2019

**No. 01/2019-Union Territory Tax**

**S.O. 636(E).**—WHEREAS, section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that—

(i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;

(ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent. of turnover in a State or Union territory in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;

AND WHEREAS, section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 read with clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1) of the said Act, if, save as otherwise provided in the said sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of section 10 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 26 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Union Territory Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017, No. 01/2017 - Union Territory Tax, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 3329 (E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Union Territory Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account -
  - (i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10 of the said Act;
  - (ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition Scheme.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.